संक्षिप्त समाचार

भेड़-चरवाहे से तुलना, उत्तराखंड गए बागियों पर खूब बरसे मुख्यमंत्री सुक्खू

मंडी, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के छह बागी विधायक तीन निर्दलीयों के साथ उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्हें एक होटल में ठहराया गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों पर तीखा हमला बोलते हुए इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। सीएम सुक्खू ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि विधायकों को इस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, जैसे चरवाहा भेड़ों को हांकता है। इस बीच एक केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि सुक्खू की सरकर गिर जाएगी। मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा छह अयोग्य कांग्रेस विधायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रही है। इन विधायकों ने पार्टी को धोखा दिया है। केंद्रीय मंत्री के सरकार गिरने के दावे पर पलटवार करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। बताया जाता है कि ये सभी विधायक शुक्रवार को देर रात एक चार्टर्ड फ्लाइट से पंचकुला से ऋषिकेश पहुंचे थे। ये होटल ताज में ठहरे हैं। बागी विधायकों के साथ हिमाचल प्रदेश भाजपा के दो विधायक विक्रम ठाकुर और त्रिलोक जमवाल भी मौजूद हैं। वहीं होटल ताज के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल में पहले से बुकिंग कराने वालों को ही एंट्री दी जा रही है। उसके अलावा अन्य को होटल परिसर में दाखिल होने इजाजत नहीं दी जा रही है।

गरीबी को मात देकर मजदूर का बेटा बना आर्मी ऑफिसर

मुंबई, एजेंसी। धारावी कोलीवाड़ा के लिए गर्व का पल आया जब उनके बीच गरीबी में पला मजदूर का बेटा उमेश दिलिराव कीलू भारतीय सेना में अफसर के पद पर तैनात हुआ। उनकी मां और बहन सहित परिवार के नौ सदस्यों ने चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में शनिवार की पासिंग आउट परेड में भाग लिया। आर्मी की वर्दी पहनने से पहले तक उमेश ने गरीबी से आमने-सामने की लड़ाई लड़ी। 2023 में लकवाग्रस्त पिता की मौत हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक, उमेश ने कहा, मेरे पिता एक पेंटर थे। 2013 में लकवाग्रस्त हो गए और मार्च 2023 में मुझे सेना प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने से एक दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। आज मैंने अपना 11 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया और सेना में एक कमीशन अधिकारी बन गया। उमेश ने गरीबी को काफी नजदीक से देखा है। लेकिन उसके दृढ़ निश्चय और लगन ने यह मुकाम दिलाया है। आर्थिक तंगी के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त की और एक स्थानीय साइबर कैफे में काम किया। उमेश को टाटा ट्रस्ट, पीएफ डावर ट्रस्ट और महालक्ष्मी ट्रस्ट से भी सहायता मिली। उमेश ने आईटी में बीएससी पूरी की और कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ली। उन्होंने बताया, मैंने तीन साल तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी काम किया और उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल में भी काम किया।

बंगाल में रामनवमी के दिन सार्वजनिक अवकाश रहने की घोषणा

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तृणमूल सरकार ने 2011 में राज्य की सत्ता में आने के बाद पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय, उनके सहयोगी संगठन और उपक्रम 17 अप्रैल को बंद रहेंगे।पिछले कुछ वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूसों को लेकर हिंसा की घटनाएं हुई हैं।पिछले साल रामनवमी जुलूस को लेकर कम से कम तीन जगहों से हिंसा की खबरें आई थीं, जिसकी जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है।पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि रामनवमी पर छुट्टी घोषित नहीं करने के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री की आलोचना की थी, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है।भाजपा के आईटी सेल प्रमुख और पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता जो हर बार जय श्रीराम के नारे सुनकर गुस्से से नीली हो जाती थीं, उन्होंने आखिरकार राज्य में रामनवमी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किए एक संदेश में कहा, ममता ने अपनी हिंदू विरोधी छवि को सुधारने के लिए ऐसा किया है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है... इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव न हो।

अगर लोग एक-दूसरे से लड़ेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा- सीजेआई चंद्रचूड़

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत के प्रधान न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि देश में समानता को बनाए रखने के लिए आपसी बंधुता जरूरी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, हमें संविधान की भावना के अनुरूप एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। बीकानेर के महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, हमारे संविधान निर्माताओं के मन में मानवीय गरिमा का सर्वोच्च महत्व था।

उन्होंने कहा, डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में यह सुनिश्चित किया कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के साथ साथ बंधुता और व्यक्ति की गरिमा की भावना को भी संविधान बढ़ावा दे। उन्होंने स्वतंत्रता व समानता के हनन के खिलाफ बंधुता को वास्तविक सुरक्षा कवच माना व उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया। प्रधान न्यायाधीश के मुताबिक, कहने का मतलब यह है कि देश में समानता को बनाए रखने के लिए आपसी बंधुता जरूरी है। अगर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे

तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, इसलिए जब हम हमारा संविधान, हमारा सम्मान कहते हैं तो हमें इस बात पर भी जोर देना होगा कि हम देश में बंधुता व भाईचारे को भी बढ़ावा दें। इन भावनाओं को अपने निजी जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने कहा, देश के नागरिकों को यह भी समझना होगा कि एक तरफ जहां संविधान उनके अधिकारों की बात करता है, दूसरी तरफ यह भी उम्मीद करता है कि देश के नागरिक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान में ही नागरिकों के दायित्व का जिक्र है, जिनमें संविधान का सम्मान करना, सामाजिक सौहार्द्र व बंधुता को बढ़ावा देना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को आत्मसात करना आदि शामिल है। उन्होंने कहा, संविधान की भावना के अनुरूप हमें एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान और उसके मूल्यों से लोगों का परिचय करवाने में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान समावेशी तौर पर बनाया गया था। कानून के समक्ष समानता का अधिकार संविधान देता है। इसमें निहित सिद्धांत व अधिकार सभी नागरिकों पर लागू होते हैं चाहे उनकी पृष्ठभूमि, धर्म, जाति, लिंग या कोई अन्य विशेषता कुछ भी हो। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान की ये कई विशेषताएं उसे सभी समूहों के बीच स्वीकार्य बनाती हैं। देश के सभी लोगों विशेषकर ग्रामीणों को संविधान से परिचित कराने की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने कहा, हमारा देश आज भी गांवों में बसता है। उनमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हमें संविधान एवं इसके मूल्यों से परिचित कराना है। जब तक संविधान की बात देश के गांवों तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा, संविधान की भावनाओं को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमारा संविधान, संविधान निर्माताओं ने लगभग तीन साल की अनवरत तपस्या से निर्मित किया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि इसकी ज्ञानेंद्रियां हैं। हर दिन करोड़ों सपने ... कला, विज्ञान, वाणिज्य, सेवा, राजनीति एवं शासन के क्षेत्र में, योग्यता के बल पर साकार होते हैं। यह संविधान की देन है जिससे करोड़ों लोगों के सपने साकार हो रहे हैं। यह संविधान की ही देन है कि सभी लोगों को अपने सपने देखने का मौका मिला है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारतीय संविधान के सामने कई चुनौतियां थीं। उन्होंने कहा कि विविधता से भरे समाज को साथ लेकर चलने की चुनौती, विभाजन के बाद बदली स्थिति में खुद को प्रासंगिक रखने की चुनौती एवं सबसे महत्वपूर्ण.. लोगों के जीवन में महत्व बनाए रखने की चुनौती थी। हमारा संविधान इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए पचहत्तर वर्ष से हमें प्रेरित व मार्गदर्शित कर रहा है। हमारा संविधान, हमारा सम्मान यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है।

सत्ता में धार्मिक व्यक्ति देता है अच्छे परिणाम, यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जज ने की जमकर तारीफ

बरेली, एजेंसी। यूपी के बरेली के एडिशनल सेशंन जज रवि कुमार दिवाकर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सत्ता में जब कोई धार्मिक व्यक्ति बैठता है तो परिणाम अच्छे आते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बताया। जज ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना दार्शनिक राजा प्लेटो के उस विचार से की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता का मुखिया एक धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का जीवन भोग का नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का होता है। जज ने कहा, इसका उदाहरण हैं महान सिद्धपीठ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत बाबा योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने उपरोक्त अवधारणा को सच साबित कर दिया है। अदालत की सुनवाइयों को कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, जज दिवाकर ने कहा कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता के आसन पर बैठता है तो वह बहुत अच्छे परिणाम देता है, जैसा कि दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की अवधारणा के बारे में बताया है। प्लेटो ने कहा था कि हमारे नगर-राज्य में तब तक दुखों का कोई अंत नहीं होगा जब तक इसमें कोई दार्शनिक राजा न हो। बता दें कि जस्टिस दिवाकर ने यह टिप्पणियां साल 2010 में बरेली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मुस्लिम मौलवी मौलाना तौकीर रजा खान को तलब करने के दौरान कीं। जज ने कहा कि देश में शायद ही कभी दंगा करने वाले मास्टरमाइंड को सजा मिली हो। जज ने यह भी कहा कि यदि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो आरोपी मौलाना तौकीर ने बरेली में एक और दंगा भड़का दिया होता। साल 2022 में जज दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का बचाव करते हुए जज ने कहा कि उन्होंने जो आदेश पारित किया था, वह कानून के हिसाब से ही किया गया था। जज ने अपने और परिवार की सुरक्षा की चिंता भी जताई। उन्होंने कहा, मेरे और मेरे परिवार में डर का माहौल इस तरह का बना हुआ है कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। परिवार के सभी लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। घर से निकलने को लेकर भी कई बार सोचना पड़ता है। मेरी मां को मेरी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता होती है।

उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और झटका, हरक सिंह की पत्नी लक्ष्मी राणा ने दिया इस्तीफा

देहरादून/रुद्रप्रयाग, एजेंसी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। वहीं कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत के साथ ही ईडी की रडार पर आईं लक्ष्मी राणा से भी पूछताछ की गई थी। ईडी पाखरो टाइगर सफारी घोटाले के मामले में उनके आवास पर छापेमारी कर चुकी है। उनके लॉकर से ईडी को 48 लाख रुपये की ज्वेलरी और संपत्ति के दस्तावेज मिले थे, जिसे लेकर उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लक्ष्मी राणा ने इस्तीफे की वजह पार्टी द्वारा बुरे समय में उनका साथ न देने की बात कही है। उन्होंने लिखा है, हाल ही में मेरे घर और प्रतिष्ठान पर राजनीतिक द्वेष के चलते ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई। हालांकि मैं जानती हूं कि ये कानूनी प्रक्रिया है, किंतु पार्टी की तरफ से मेरे खिलाफ इस राजनीतिक द्वेष के बारे में न कोई प्रतिक्रिया आई और न ही किसी ने इस दुख की घड़ी में मुझे ढाढ़स बंधाया।लक्ष्मी राणा 1997 से 2001 तक जखोली की ब्लॉक प्रमुख रहीं। साल 2002 से 2007 तक वह दर्जाधारी रहीं। 2014 से 2019 तक रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। लक्ष्मी राणा ने 2017 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा।

अगले हफ्ते हो सकता है लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान, साथ में ही जम्मू-कश्मीर इलेक्शन की भी अटकलें

नईदिल्ली, एजेंसी। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल, चुनाव आयोग सोमवार से बुधवार तक जम्मू-कश्मीर का दौरा करने वाला है। इस दौरान यह देखा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्शन कब कराए जा सकते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के दौरे के तुरंत बाद आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि आम चुनाव की घोषणा गुरुवार या शुक्रवार को हो सकती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिसंबर में निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ असेंबली इलेक्शन कराए जा सकते हैं। आम चुनाव से पहले देश भर में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और

उनकी आवाजाही को लेकर चर्चा जारी है। इस मामले पर गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ ईसी ने शुक्रवार को बैठकें कीं। समझा जाता है कि निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराने की संभावना पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं का कार्यकाल जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में यहां विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जा सकते हैं। आदर्श आचार संहिता से पहले बड़े-बड़े राजनीतिक वादे मालूम हो कि चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले राजनीतिक पार्टियां बड़े-बड़े वादे कर रही हैं और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जा रहा है। समझा जा रहा है कि अप्रैल-मई में लोकसभा इलेक्शन हो सकता है जिसे ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टियों की सक्रियता तेज हो गई है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ के 43 भाजपा नेताओं को दी गई सुरक्षा, किसे मिली वाय प्लस सिक्योरिटी, अमित शाह से लगाई थी गुहार

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर के 43 भाजपा नेताओं को सुरक्षा दी है। दरअसल, हाल ही में बस्तर के बीजापुर के भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि नक्सलियों द्वारा भाजपा नेताओं को टारगेट किया जा रहा है।

शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार के पुलिस विभाग की ओर से सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, और नारायणपुर जिले के 43 नेताओं को सुरक्षा देने का आदेश जारी किया गया है। जिन नेताओं को सुरक्षा दी गई है उसमें सुकमा से भाजपा के जिलाध्यक्ष धनीराम बारसे को ङ्क+ व सुकमा के अन्य भाजपा नेताओं को वाय प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है।

वहीं बीजापुर भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मूदलियार समेत अन्य भाजपा नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। साथ ही दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर व कांकेर के जिले के कई भाजपा नेताओं को भी एक्स श्रेणी की सुरक्षा गई हैं।

गौरतलब है कि बीते दो सप्ताह में नक्सलियों ने बीजापुर जिले में लगातार दो

भाजपा नेताओं की हत्या कर दी थी। जिसके बाद बीजापुर में भाजपा नेता नक्सलियों के खौफ में थे। वहीं चुनाव से पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के अलग-अलग जिलों के नेताओं को सुरक्षा दे दी है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बस्तर के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के भाजपा नेताओं को अस्थायी सुरक्षा दी गई थी। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद सुरक्षा हटा ली गई। हाल में नक्सलियों ने बीजापुर में दो भाजपा नेताओं की हत्या कर दी। जिसके चलते बस्तर के भाजपा नेताओं ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ही सुरक्षा देने की गुहार लगा दी। इस मामले में भाजपा सरकार पर कांग्रेस ने तंज कसना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अपनी ही सरकार में भाजपा का नेता डरा हुआ महसूस कर रहा है।

वहीं इससे पहले नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में बीते वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई भाजपा नेताओं की हत्या कर दी थी। जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए थे जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को केंद्र से सीधे सुरक्षा मुहैया कराई थी। इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार है और लगातार भाजपा नेताओं पर नक्सलियों के हमलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने 43 भाजपा के नेताओं को सुरक्षा देने का आदेश जारी किया है। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में सुकमा जिले से 6, बीजापुर जिले से 10, दंतेवाड़ा से 17, जगदलपुर से 4, कोंडागांव से 1, कांकेर से 4 व नारायणपुर जिले से 1 भाजपा नेता को सुरक्षा दी गई है।

भाजपा के कार्यक्रम में बांटा जा रहा था बर्तन, अचानक मच गई भगदड़, एक महिला की मौत

नागपुर , एजेंसी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में निर्माण श्रमिकों के लिए भाजपा की ओर से शनिवार को बर्तन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भगदड़ मचने से 65 वर्ष की एक महिला की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सहित विपक्षी नेताओं ने इस घटना पर भाजपा की आलोचना की। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। कोतवाली थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब साढ़े 10 बजे रेश्मिबाग क्षेत्र के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में हुई, जहां भाजपा की नागपुर इकाई की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पार्टी ने महाराष्ट्र भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को बुलाया था। इन लोगों को बर्तन और अन्य जरूरी वस्तुएं वितरित करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। अधिकारी ने बताया कि लोग सुबह 5 बजे के आसपास ही कार्यक्रम स्थल के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए और लाभार्थियों के लिए द्वार खोले जाने तक भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही भीड़ अंदर घुसी कुछ महिलाएं गिर गईं और उन्हें चोटें आईं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भगदड़ में मनुबाई तुलसीराम राजपूत गिर गईं और उन्हें आनन-फानन में एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि 4 अन्य महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं।

दुर्घटनावश मौत को लेकर मामला दर्ज : अधिकारी ने बताया कि घटना के समय कार्यक्रम स्थल पर महिला कर्मियों समेत कम से कम 50 पुलिसकर्मी तैनात थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटनावश मौत का एक मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। शहर भाजपा अध्यक्ष जीतेंद्र उर्फ बंटी कुकड़े ने दावा किया कि महिला की मौत भगदड़ से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। उन्होंने बताया कि लोग अप्रत्याशित संख्या में एकत्र हुए और वरिष्ठ नागरिक महिला गर्मी और दम घुटने के कारण बेहोश हो गईं। उन्होंने बताया कि उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि कुप्रबंधन के कारण महिला की जान गई। उन्होंने मांग की कि आयोजनकर्ताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के महासचिव विशाल मुत्तेमवार ने भी घटना की निंदा की है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन भाजपा पदाधिकारियों के साथ-साथ आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई करे।

कोरबा लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस-बीजेपी की दो महिला दिग्गज आमने-सामने

कोरबा, एजेंसी। छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपने-अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया तो वही उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत को कोरबा सीट से उम्मीदवार बनाया है। कोरबा लोकसभा ऐसी सीट है जहां कभी किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा है। इस सीट पर अब तक होते आ रहे चुनाव में लगातार किसी एक पार्टी को जीत नहीं मिली है। आपको बताते हैं कोरबा लोकसभा सीट के बारे में। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से कोरबा एक महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यहां से वर्तमान में सांसद छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी ज्योत्सना चरणदास महंत हैं। साल 2008 में परिसीमन के बाद कोरबा लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। उसके पहले यह लोकसभा सीट जांजगीर-चांपा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती थी।

कब कौन जीता चुनाव : कोरबा लोकसभा सीट पर पहली बार साल 2009 में चुनाव हुए थे। इस सीट से पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चरणदास महंत को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने करुणा शुक्ला को यहां से मैदान में

उतारा था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चरण दास महंत चुनाव जीत कर सांसद बने थे। वही साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कोरबा सीट से

भारतीय जनता पार्टी के डॉ बंसीलाल महतो चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। भाजपा के बंसीलाल महतो ने कांग्रेस पार्टी के चरण दास महंत को लोकसभा के चुनाव में हराकर सांसद बने थे। इस लोकसभा चुनाव में चरण दास महंत महज 4000 वोट के अंतर चुनाव हार गए थे। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा के चुनाव में कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ज्योत्सना चरण दास महंत को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने भाजपा प्रत्याशी को चुनाव में हराते हुए सांसद बनी थी। वर्तमान में कोरबा लोकसभा सीट से ज्योत्सना महंत सांसद हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर अगर नजर डालें तो, छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट में साल 2019 में हुए चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कोरबा सीट से सांसद रहे चरण दास महंत की पत्नी ज्योत्सना चरण दास महंत को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिनंद दुबे को चुनाव के मैदान में उतारा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कोरबा सीट से कांग्रेस पार्टी की ज्योत्सना चरण दास महंत ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव में हराते हुए सांसद बनी थी। कांग्रेस पार्टी की ज्योत्सना महंत को 5.23 लाख वोट मिले थे। वहीं भाजपा के ज्योतिनंद दुबे 4.97 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस की उम्मीदवार ने भाजपा के दुबे को 26249 वोट से चुनाव हारते हुए लोकसभा पहुंची थी।